हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084.

www.rashtriyaswabhimaan.com

● वर्ष : 17 ● अंक : 159 ● मुंबई, गुरुवार, 12 फरवरी 2026 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

खबर संक्षेप

राज्य विश्वविद्यालयों में पारदर्शी शिक्षक भर्ती का नया अध्याय शुरू

मुंबई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विस्तृत कार्यप्रणाली की घोषणा करते हुए बताया कि अब सहायक प्राध्यापक समेत विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार की अंकसूची, जिसमें इंटरव्यू और अन्य मानदंडों के तहत दिए गए अंक शामिल होंगे, संबंधित विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इस निर्णय को लंबे समय से उठ रही पारदर्शिता की मांग का सकारात्मक उत्तर माना जा रहा है। मंत्री पाटिल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भर्ती को लेकर अक्सर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी की शिकायत की थी। अब अंक सार्वजनिक करने से चयन प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत होगा और किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति कम होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और इसके लिए योग्य शिक्षकों की निष्पक्ष भर्ती अत्यंत आवश्यक है। नई कार्यप्रणाली इसी दिशा में एक ठोस पहल है। इस निर्णय से सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को मिलने जा रही है, जो वर्षों से तासिका, संविदा या एडहॉक आधार पर कार्यरत हैं। लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे इन शिक्षकों के सामने स्थायी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी। अब उनके अनुभव को पात्रता के लिए मान्य किया जाएगा, जिससे उन्हें नियमित पदों के लिए आवेदन करते समय उचित लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके अनुभव और योगदान को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। नई नीति के तहत अनुभव को अंक देने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। इससे न केवल अनुभवी शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि संस्थानों को भी ऐसे उम्मीदवार मिलेंगे जिनके पास शिक्षण का व्यावहारिक अनुभव हो। शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि यह कदम विश्वविद्यालयों में स्थायित्व और गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा देगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स, सोना और विदेशी मुद्रा जब्त

मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट, कस्टम्स जोन–III के अधिकारियों ने नए साल की शुरुआत से लेकर फरवरी के दूसरे सप्ताह तक लगातार सतर्कता बरतते हुए तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 के बीच ड्यूटी के दौरान स्पॉट चेक, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) प्रोफाइलिंग और खुफिया सूचना के आधार पर की गई जांच में करोड़ों रुपये मूल्य के ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा जब्त की गई। इन कार्रवाइयों से अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। सबसे बड़ी कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ दर्ज की गई। कुल सात मामलों में हाइड्रोपोनिक वीड की बड़ी खेप पकड़ी गई, जिससे एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार बैंकॉक से मुंबई पहुंचे सात यात्रियों को संदेह के आधार पर रोका गया। विस्तृत तलाशी और जांच के दौरान उनके पास से कुल 13.256 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 13.256 करोड़ रुपये आंकी गई है। सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है। हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी पिछले कुछ समय से चिंता का विषय बनी हुई है। यह उच्च गुणवत्ता वाली मादक सामग्री विशेष तकनीक से उगाई जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि प्रोफाइलिंग तकनीक और व्यवहार विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध यात्रियों की पहचान की गई, जिससे यह बड़ी खेप पकड़ में आई। अधिकारियों के अनुसार आगे की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स की सप्लाई चेन किन देशों और शहरों तक फैली हुई है।

चार साल बाद खत्म हुआ प्रशासकीय राज:, मुंबई मनपा में महायुति की वापसी

रितू तावड़े मेयर और संजय घाडी उपमहापौर निर्विरोध, विपक्ष ने उठाए सवाल

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में चार वर्षों के लंबे प्रशासकीय शासन के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की वापसी हो गई है। भाजपा की रितू तावड़े को महापौर और शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय घाडी को उपमहापौर पद पर निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति ने राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया। महायुति ने इसे "मुंबईकरों के विश्वास की जीत" बताते हुए लोकाभिमुख और पारदर्शी प्रशासन देने का भरोसा दोहराया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों को अब महानगरपालिका के माध्यम से और गति दी जाएगी। उन्होंने रितू तावड़े को अनुभवी और जुझारू नेतृत्व बताते हुए विश्वास जताया कि वे मुंबईकरों के मुद्दों को प्राथमिकता देंगी। उपमहापौर संजय घाडी के अनुभव का भी लाभ शहर को मिलेगा। बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी का उल्लेख करते हुए फडणवीस ने कहा कि महानगरपालिका को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप दिशा दी जाएगी और राज्य सरकार पूरी ताकत से नए नेतृत्व के साथ खड़ी रहेगी।

हालांकि, इस राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह जीत लोकतांत्रिक मजबूती की नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों की देन है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि शहर आज भी गड्ढों, जलभराव, महंगाई, पानी की कमी और ट्रैफिक अव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके अनुसार, सिर्फ सत्ता परिवर्तन से हालात नहीं बदलेंगे, जब तक ठोस नीतिगत सुधार और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होती।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी प्रक्रिया और दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएमसी पर "राजनीतिक कब्जा" किया गया है। पार्टी प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत का नाम लेकर राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है, जबकि शहर के बुनियादी मुद्दों पर स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं रखा गया है। उन्होंने वित्तीय पारदर्शिता और बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

इसी बीच, अजित पवार की दुर्घटना में मृत्यु को लेकर उठे सवालों पर भी सियासत गरमा गई है। रोहित पवार द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यदि किसी के मन में संदेह है तो उसका समाधान होना चाहिए और निष्पक्ष जांच जरूरी है। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने भी स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में सच्चाई सामने आना जनता के विश्वास के लिए आवश्यक है। मुंबई मनपा में नई टीम के सामने अब बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने, मानसून से निपटने, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब नजर इस बात पर रहेगी कि महायुति नेतृत्व अपने वादों को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से उतार पाता है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का क्या जवाब देता है।

बीड में हुआ शिक्षा घोटाला, धनंजय मुंडे की संस्था का कॉलेज का आया नाम!

बीड। बीड जिले के परली में एक चौंकाने वाला शिक्षा घोटाला सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, क्षेत्र के 'यशवंतराव चव्हाण कनिष्ठ महाविद्यालय' से जुड़ी 12वीं की परीक्षाओं में बड़ी अनियमितताएं पकड़ी गई हैं। यहां छात्रों के हॉल टिकट पर परीक्षा केंद्र कुछ और दर्शाया गया है, जबकि परीक्षा किसी अन्य स्थान पर ली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि केवल कागजों पर मौजूद इस कॉलेज का संचालन पूर्व नेता धनंजय मुंडे की नाथ शिक्षण संस्था द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में इस कॉलेज का कोई ठोस अस्तित्व नजर नहीं आता। न यहां इमारत है, न कक्षाएं, न मैदान और न ही छात्र। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस कॉलेज को मान्यता कैसे मिली।परली तालुका में 11 केंद्रों पर करीब 5000 छात्र बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन यशवंतराव चव्हाण कनिष्ठ महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा शारदा माध्यमिक विद्यालय, जिरेवाडी में ली जा रही है, जो अधिकृत परीक्षा केंद्र नहीं है। इसके लिए स्कूल के नियमित छात्रों और शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई।स्थानीय शिक्षा अधिकारी गिरी ने माना कि परली में कोई भी परीक्षा केंद्र संवेदनशील नहीं है। इसके बावजूद मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र बदले जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों द्वारा न तो स्थल का निरीक्षण किया गया और न ही इस अनियमितता पर समय रहते ध्यान दिया गया। ऐसे में अब इस मामले में जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

बालासाहेब के सपनों के साथ मुंबई बनेगी वैश्विक फिनटेक हब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी विकास की गारंटी

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका में महायुति की महापौर ऋतु तावड़े और उपमहापौर संजय घाडी के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को वैश्विक फिनटेक हब बनाने का बड़ा संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में शिंदे ने कहा कि वंदनीय बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए महायुति सरकार प्रतिबद्ध है। शिंदे ने कहा कि मुंबईकरों ने महायुति को समर्थन देकर विकास को चुना है। उनके अनुसार, पिछले 25 वर्षों में मुंबई अपेक्षित विकास से वंचित रही, लेकिन महायुति सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में शहर के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि महापौर ऋतु तावड़े और उपमहापौर संजय घाडी जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में महानगरपालिका जनहित के कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि मुंबई को विश्वस्तरीय फिनटेक हब बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई के लक्ष्य का जिक्र करते हुए बताया कि एसआरए और क्लस्टर योजनाओं के माध्यम से 40 लाख मुंबईकरों को उनका अधिकार का घर देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार खड्डेमुक्त, प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और नशामुक्त मुंबई के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि महायुति सरकार और महानगरपालिका मिलकर मुंबई को नई दिशा और नई गति देंगे।

एपस्टीन फाइल्स पर मचा सियासी घमासान, राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी ने आनन फानन में दी सफाई

नई दिल्ली। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान एपस्टीन फाइल्स का मुद्दा उठने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि अमेरिकी न्याय विभाग के पास मौजूद एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम शामिल है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा गया और एपस्टीन से उनकी मुलाकात किसने करवाई।

राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जेफरी एपस्टीन से मुलाकात हुई थी, लेकिन यह मुलाकात वर्ष 2009 में उस समय हुई जब वे अमेरिका में भारत के राजदूत थे और अंतरराष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट (IPI) के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

पुरी ने कहा कि एपस्टीन फाइल्स आपराधिक मामलों से संबंधित हैं, जिनमें गंभीर आरोप शामिल हैं, लेकिन उनकी मुलाकात का इन मामलों से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उपलब्ध ईमेल और दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं और मुलाकातें आधिकारिक दायरे में थीं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि नवंबर 2014 में, जब वे एक निजी नागरिक थे, तब एपस्टीन से जुड़े एक व्यक्ति ने उनकी मुलाकात लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन से करवाई थी। उस समय भारत में निवेश और संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई थी।

संसद के बाहर भी राहुल गांधी ने अपने आरोप दोहराते हुए कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग के पास उपलब्ध फाइल्स में संबंधित नाम दर्ज हैं। वहीं, सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है।

एपस्टीन फाइल्स को लेकर उठे इस विवाद के बाद संसद के भीतर और बाहर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

चीन, अमेरिका और एपस्टीन फाइल्स पर पीएम की चुप्पी क्यों?'- वर्षा गायकवाड़ का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

नयी दिल्ली। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीन, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, एपस्टीन फाइल्स और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की पुस्तक जैसे मुद्दों पर कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आना चिंताजनक है।

गायकवाड़ ने भारत-अमेरिका व्यापार करार को लेकर आशंका जताई कि इससे देश के किसानों और कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शून्य प्रतिशत शुल्क और भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत कर लगाए जाने की चर्चा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे।

चीन से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सीमाई हालात जैसे संवेदनशील विषयों पर संसद और देश को भरोसे में लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सत्र के दौरान इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए इसे "उचित नहीं" बताया।

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा बैनर दिखाए जाने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गायकवाड़ ने कहा कि विपक्ष पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उनका कहना था कि सांसदों ने केवल बैनर प्रदर्शित किया, किसी प्रकार की अनुचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पूछा कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का यह तरीका भी गलत माना जाएगा।

कांग्रेस सांसद के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

देश की चिंता छोड़िए, पहले अपना घर संभालिए' लोकसभा में राहुल गांधी पर बरसे डॉ. श्रीकांत शिंदे

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शिवसेना संसदीय दल के नेता और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश के अधिकांश राज्यों में चुनाव हार चुकी है, उसे पहले अपना संगठन संभालना चाहिए, उसके बाद देश और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर टिप्पणी करनी चाहिए। डॉ. शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने आर्थिक और रक्षा नीतियों को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वे तथ्यों से परे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के भीतर और विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

अपने भाषण की शुरुआत में डॉ. शिंदे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार नौवीं बार बजट पेश करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनता ने तीन बार एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है और तीसरी बार सरकार तीन गुना विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार, 'विकसित भारत 2047' के विजन के तहत युवा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार को केंद्र में रखकर बजट तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुंबई में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए भी 10 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं तथा औद्योगिक क्षेत्रों के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. शिंदे ने कहा कि वर्ष 2013-14 में देश का बजट 16.50 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 53.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने अपनी आत्मकथा में तत्कालीन सरकार द्वारा आरबीआई पर दबाव डालने का उल्लेख किया है।

रक्षा मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध से संबंधित ब्रुक्स रिपोर्ट संसद से छिपाई गई थी। उन्होंने अक्साई चीन और कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है।

पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए डॉ. शिंदे ने राज्य सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि वर्ष 2011 से 2025 के बीच 6400 कंपनियां बंगाल से बाहर चली गईं और घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर FIR, प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र करने के बाद सियासी हंगामा मच गया है। दिल्ली पुलिस ने किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में FIR दर्ज की है। इस कार्रवाई पर शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को घेरा और इसे डराने-धमकाने की रणनीति बताया।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार की कार्रवाई से संदेश स्पष्ट है कि "सच मत बोलो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो"। उन्होंने कहा कि अब सेना के पूर्व प्रमुख की किताब पढ़ना भी राजद्रोह, राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक कृत्य माना जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' का प्रकाशन संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस किताब की PDF कॉपी कुछ वेबसाइटों पर मौजूद थी और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसा दिखाया गया कि यह बिक्री के लिए उपलब्ध है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किताब का प्रकाशन अभी तक संबंधित अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त नहीं होने के कारण FIR दर्ज की गई है। इस मामले ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है।

संपादकीय

हितधारक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रॉड सीधे-सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है।

इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले-भाले लोगों को जिस तरह साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

चीन भी आ गया लाइन पर, UNSC में भारत के दावे का किया समर्थन, व्यापार समझौता करने को भी तैयार

> करीब 4 वर्ष तक चले पूर्वी लद्दाख गतिरोध ने दोनों देशों के संबंधों को झकझोर दिया था। उसके बाद हुए सीमा समझौते और शीर्ष नेतृत्व की बैठकों के फल अब सामने आने लगे हैं। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही व्यापक रिश्तों की बुनियाद है।

भारत और चीन के बीच रिश्तों की जमी बर्फ अब पिघलने लगी है और यह बदलाव केवल सीमा तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि व्यापार, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन तक फैलता नजर आ रहा है। नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशु के बीच हुई सामरिक संवाद बैठक ने यह साफ कर दिया कि दोनों देश टकराव की लंबी थकान के बाद अब ठोस लाभ की राह तलाश रहे हैं। बातचीत का मुख्य आधार रहा व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखना।हम आपको याद दिला दें कि करीब 4 वर्ष तक चले पूर्वी लद्दाख गतिरोध ने दोनों देशों के संबंधों को झकझोर दिया था। उसके बाद हुए सीमा समझौते और शीर्ष नेतृत्व की बैठकों के फल अब सामने आने लगे हैं। दोनों पक्षों ने माना कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही व्यापक रिश्तों की बुनियाद है। इसी सोच के साथ द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी अड़चनों को राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सुलझाने पर जोर दिया गया।

बैठक में वायु सेवा समझौते को जल्द नया रूप देने, जन से जन संपर्क बढ़ाने और प्रवेश अनुमति पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भरोसे की बहाली का संकेत माना गया और इसके दायरे को आगे बढ़ाने की आशा जताई गई।

सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात रही चीन का यह कहना कि वह भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा को समझता और उसका सम्मान करता है। यह रुख पहले के ठंडे या विरोधी रवैये से अलग माना जा रहा है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं और हर एक के पास वीटो शक्ति है। ऐसे में किसी नए स्थायी सदस्य के रास्ते में इन पांचों की सहमति निर्णायक होती है। पहले चार स्थायी सदस्यों ने अलग अलग समय पर भारत के दावे का समर्थन जताया है, जबकि चीन का रुख अस्पष्ट या ठंडा रहा। अब बीजिंग की यह नरमी नई चर्चा को जन्म दे रही है।

चीन ने यह भी कहा कि बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थिति में दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी साझेदार के रूप में देखना चाहिए। दोनों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, ग्लोबल साउथ की एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात दोहराई। साथ ही भारत की इस वर्ष की ब्रिक्स अध्यक्षता और भारत में होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए चीन ने समर्थन जताया।

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते आगे बढ़ाए हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बना रहा है। ऐसे में चीन का भारत की ओर व्यापार और कूटनीति का हाथ बढ़ाना केवल सद्भाव नहीं, बल्कि रणनीति भी माना जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं यदि टकराव कम कर सहयोग बढ़ाती हैं, तो एशिया ही नहीं, पूरे विश्व का शक्ति गणित बदल सकती हैं।

पिछले छह महीनों में भारत चीन संबंधों में जो सुधार दिखा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातें, सैन्य स्तर पर संवाद और आर्थिक संपर्क की बहाली शामिल है। हालांकि अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर संवाद की पटरी पर लौटना अपने आप में बड़ा बदलाव है।

देखा जाये तो भारत चीन रिश्तों में यह नरमी केवल दोस्ती की कहानी नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ की राजनीति है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और सामरिक समीकरण ने बीजिंग को संकेत दिया है कि नई दिल्ली अब विकल्पों से भरपूर है। ऐसे में चीन का लहजा बदलना स्वाभाविक भी है और मजबूरी भी। वह नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमे की ओर झुक जाए और एशिया में उसके लिए संतुलन बिगड़ जाए।

भारत के लिए भी यह मौका है, पर खतरे से खाली नहीं। चीन के शब्द मधुर हो सकते हैं, पर उसकी नीति हमेशा अपने हित के इर्द गिर्द घूमती है। सीमा पर शांति की बात स्वागत योग्य है, पर जमीन पर सख्त चौकसी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। इतिहास बताता है कि भरोसा और सतर्कता दोनों साथ साथ चलाने पड़ते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर चीन का नरम संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना सुधार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन केवल समझने और सम्मान करने से काम नहीं चलेगा, खुला और स्पष्ट समर्थन ही असली कसौटी होगा। बहरहाल, यदि भारत और चीन सच में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर सहयोग का रास्ता निकाल लेते हैं, तो इसके वैश्विक और क्षेत्रीय भूराजनीतिक निहितार्थ गहरे होंगे। एशिया में तनाव घट सकता है, आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर हो सकती हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो सकती है। इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी नया बल मिलेगा, जहां पश्चिम का वर्चस्व अकेला निर्णायक न रहे। पर अंतिम सवाल यही है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या हालात बदलते ही फिर तल्खी लौट आएगी। भारत को इस नए दौर में आत्मविश्वास, आर्थिक शक्ति और सैन्य तैयारी के साथ कदम बढ़ाना होगा। दोस्ती की मेज पर हाथ मिलाते समय भी सीमा पर नजर और दिमाग, दोनों खुले रखने होंगे। यही परिपक्व शक्ति की पहचान है।

सरोकार

आत्मविकास से उपजता है सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा

प्राचीन चीन की सांस्कृतिक धारा में कन्फ्यूशियस का नाम एक ऐसे दार्शनिक के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने मनुष्य को बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक परिष्कार का महत्व समझाया। वे मानते थे कि समाज में प्रतिष्ठा पाने का मार्ग किसी पद, शक्ति या आग्रह से नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम और निरंतर कर्म से प्रशस्त होता है। एक बार वे अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। सुबह का समय था, हल्की हवा बह रही थी और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक झील के किनारे बैठे एक युवक पर पड़ी, जो अत्यंत व्यथित होकर रो रहा था।

कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को संकेत किया और स्वयं उस युवक के पास जाकर शांत स्वर में पूछा, "पुत्र, तुम्हारे हृदय में इतना क्लेश क्यों है?" युवक ने सिर उठाया, उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, "गुरुदेव, मैं एक छोटे पद पर कार्य करता हूं। मैं पूरी निष्ठा से अपना काम करता हूं, परंतु कोई मेरी बात को महत्व नहीं देता। मेरे सुझावों पर हंसी उड़ाई जाती है। जितनी अधिक मेहनत करता हूं, उतना ही उपहास सहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें, मेरी बात सुनें, पर मुझे समझ नहीं आता कि वह सम्मान कैसे प्राप्त करूं।" कन्फ्यूशियस कुछ क्षण मौन रहे। फिर वे वहीं भूमि पर बैठ गए। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर एक बड़ा वृत्त बनाया। युवक और शिष्य ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कन्फ्यूशियस बोले, "यह वृत्त समाज है—विशाल, विविध और अनेक प्रकार के स्वभावों से भरा हुआ।" फिर उन्होंने उस वृत्त के मध्य एक छोटा-सा बिंदु बनाया और कहा, "यह तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, इसलिए महत्वहीन हो। परंतु छोटा होना अपूर्ण होना नहीं है।"

युवक ने उत्सुकता से पूछा, "तो क्या केवल छोटा होना ही मेरी समस्या है?" कन्फ्यूशियस मुस्कुराए। उन्होंने उस बिंदु से बाहर की ओर कई रेखाएं खींचीं, जो वृत्त की सीमा तक पहुंच रही थीं। "देखो," उन्होंने कहा, "जब यह बिंदु स्थिर रहता है, तो वह केवल एक बिंदु है। पर जब इससे रेखाएं बाहर की ओर बढ़ती हैं, तब यह पूरे वृत्त को स्पर्श करता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा ज्ञान, धैर्य, आचरण और कर्म बाहर की ओर फैलते हैं, तब समाज स्वयं तुम्हें पहचानने लगता है।"

युवक अब ध्यान से सुन रहा था। कन्फ्यूशियस ने आगे कहा, "सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। मांगा हुआ सम्मान क्षणिक होता है और उसमें स्थायित्व नहीं होता। सच्चा सम्मान तब मिलता है जब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग स्वयं तुम्हें महत्व देने लगते हैं। पहले अपने भीतर आकार लो, अपने विचारों को स्पष्ट करो, अपने कर्मों को सुसंगत बनाओ, फिर दुनिया तुम्हें स्थान देगी।"

युवक ने धीमे स्वर में कहा, "परंतु जब लोग मेरी बात सुनते ही नहीं, तब मैं स्वयं को कैसे स्थापित करूं?" कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, "लोगों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा आचरण तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम्हारा ज्ञान गहरा होगा, तुम्हारा व्यवहार संतुलित होगा और तुम्हारा कर्म निरंतर होगा, तो समय के साथ लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जल की धारा भी चट्टान को तुरंत नहीं काटती, पर निरंतर बहती रहे तो कठोर पत्थर को भी आकार दे देती है।"

उन्होंने आगे समझाया कि अक्सर मनुष्य सम्मान को परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखने लगता है। वह सोचता है कि यदि वह परिश्रम कर रहा है तो उसे तुरंत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। परंतु समाज एक विशाल वृत्त की भांति है, जहां हर व्यक्ति अपने-अपने केंद्र में है। यदि कोई व्यक्ति अपने केंद्र से बाहर नहीं निकलता, अपने ज्ञान और संवेदनशीलता का विस्तार नहीं करता, तो वह दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता।

कन्फ्यूशियस ने युवक से पूछा, "क्या तुम केवल अपने काम तक सीमित रहते हो, या दूसरों की सहायता भी करते हो?" युवक ने संकोच से कहा, "मैं अपने दायित्व पूरे करता हूं, पर दूसरों के काम में कम ही हस्तक्षेप करता हूं।" कन्फ्यूशियस बोले, "यही तुम्हारे विस्तार का प्रारंभ है। जब तुम दूसरों के कार्य को समझोगे, उनकी कठिनाइयों में सहयोग दोगे, तब वे तुम्हें केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि आत्मसम्मान और बाहरी सम्मान में अंतर होता है। यदि व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और दृढ़ है, तो बाहरी उपेक्षा उसे विचलित नहीं करती। पर यदि भीतर ही शंका और असुरक्षा हो, तो थोड़ी-सी आलोचना भी मन को तोड़ देती है। इसलिए पहला कार्य है स्वयं को भीतर से सुदृढ़ करना। अध्ययन करो, अनुभव से सीखो, अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। जब तुम्हारा व्यक्तित्व परिपक्व होगा, तो उपहास स्वयं समाप्त हो जाएगा।

युवक के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उसने पूछा, "क्या यह प्रक्रिया बहुत लंबी होगी?" कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, "हर वृक्ष बीज से ही प्रारंभ होता है। बीज को धैर्य रखना पड़ता है। यदि वह अधीर होकर मिट्टी को दोष दे, तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हें अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करना है। जड़ें मजबूत होंगी तो शाखाएं स्वयं फैलेंगी।"

शिष्यों ने देखा कि युवक की आंखों में अब निराशा की जगह आशा थी। वह समझ चुका था कि सम्मान कोई उपहार नहीं, जिसे कोई और प्रदान कर दे। वह एक छवि है, जो निरंतर कर्म, संयम और विवेक से निर्मित होती है। उसने कन्फ्यूशियस को प्रणाम किया और कहा, "मैं अब सम्मान की याचना नहीं करूंगा। मैं स्वयं को इतना योग्य बनाऊंगा कि सम्मान मेरे पीछे आए।"

प्रकृति रक्षा के लिए कड़े कानूनी बदलावों की जरूरत

मानवता ने अपनी प्रगति की गाथा अक्सर प्रकृति की कीमत पर लिखी है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, हमने विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के ढेर तो खड़े कर लिए, लेकिन इसकी वजह से नदियों को विषाक्त नालों और हरे-भरे जंगलों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। आज जब हिमालय की नींव धंस रही है और हवा सांसों में जहर घोल रही है, तब एक तीखा सवाल सामने है - क्या अपराध इंसानों के खिलाफ ही 'संगीन' होते हैं?

इसी सवाल से एक क्रांतिकारी शब्द ने जन्म लिया - 'ईकोसाइड' यानी 'प्रकृति का नरसंहार'। जिस प्रकार विश्व ने 'जेनोसाइड' को मानवता के विरुद्ध वीभत्स अपराध मानकर दंडित किया, अब प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे इस व्यवस्थित विनाश को भी उसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी श्रेणी में रखा जाए। अब न्याय केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगलों और नदियों के लिए भी होना चाहिए, जिनका अस्तित्व हमारी लालसा की भेंट चढ़ गया।

वर्तमान परिदृश्य में 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे' का सिद्धांत अपनी सार्थकता खोकर केवल 'वैध व्यापारिक लागत' बनकर रह गया है। बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने पर्यावरण विनाश से भारी मुनाफा कमाते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को अपनी बैलेंस शीट में मामूली खर्च मानकर चुका देते हैं। इस व्यवस्था ने पैसे को संरक्षण के बजाय विनाश का 'लाइसेंस' बना दिया है। ईकोसाइड की अवधारणा इसी खामी पर प्रहार करते हुए नागरिक दायित्व को 'कठोर आपराधिक उत्तरदायित्व' में बदलने की वकालत करती है। संदेश देती है कि प्रकृति कोई 'कमोडिटी' नहीं जिसे नष्ट करके उसकी कीमत चंद रुपयों में चुकाई जा सके; बल्कि जीवंत इकाई है।

जब भोपाल गैस त्रासदी और श्रीराम फर्टिलाइजर्स जैसी भयावह घटनाएं हुईं, तो न्यायपालिका ने कानून की सीमाओं को विस्तार दिया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) के मामले में 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण दायित्व) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पष्ट किया कि यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक गतिविधि में लगा है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है, तो वह उद्योग बिना अपवाद उत्तरदायी होगा। ईकोसाइड कानून इसी 'पूर्ण दायित्व' के विचार को अगले स्तर पर ले जाता है। यह केवल क्षतिपूर्ति की बात नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही और जेल की सजा का प्रावधान करता है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों में कानून का भय और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा हो। कानूनी रूपांतरण का वह चरण जहां पर्यावरण का विनाश मानवता के खिलाफ संगीन जुर्म माना जाएगा।

इस कानूनी विमर्श का मुख्य केंद्र 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण से हटकर 'प्रकृति-केंद्रित' न्यायशास्त्र को अपनाना है। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 51ए(जी) और 21) पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य और अधिकार मानता है। लेकिन अब समय है प्रकृति के 'स्वतंत्र अधिकारों' को मान्यता देने का। ए. नागराजा (2014) और सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017) जैसे मामलों ने जानवरों और नदियों (गंगा-यमुना) को 'विधिक व्यक्ति' का दर्जा देकर नई राह दिखाई है। यदि एक नदी कानून की नजर में 'व्यक्ति' है, तो उसे प्रदूषित करना 'हत्या के प्रयास' जैसा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर ईकोसाइड को अपराध घोषित करने की मुहिम तेज हो रही है, जहां बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों ने अपने घरेलू कानूनों में इसे शामिल कर मिसाल पेश की है। वर्तमान में 'स्टॉप ईकोसाइड इंटरनेशनल' जैसे संगठन यह प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की 'रोम संविधि' में संशोधन कर ईकोसाइड को नरसंहार और युद्ध अपराधों की श्रेणी में 'पांचवां अंतर्राष्ट्रीय अपराध' घोषित किया जाए। ताकि कोई राष्ट्र या कॉर्पोरेट विकास की आड़ में पर्यावरण को अपूरणीय क्षति न पहुंचा सके।

भारत के लिए ईकोसाइड कानून अपनाना केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' के दर्शन को मानने वाले देश के लिए प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करना एक स्वाभाविक कदम है। यह कानून विकास का विरोधी नहीं, बल्कि 'जिम्मेदार और सतत विकास' का समर्थक है। यह संतुलित प्रगति की परिभाषा है जहां मानवता और प्रकृति सह-अस्तित्व में फलें-फूलें।

निश्चित रूप से, ईकोसाइड कानून के मार्ग में 'गंभीर क्षति' को परिभाषित करने और साक्ष्य जुटाने जैसी चुनौतियां हैं। इसके समाधान के लिए हमें अपने कानूनी शिक्षण में 'अर्थ ज्यूरिसप्रुडेंस' को शामिल करना होगा। अब हम जोशीमठ जैसे संकटों या दम तोड़ती नदियों को केवल 'प्राकृतिक आपदा' का लेबल न दें, बल्कि उन मानवीय निर्णयों की आपराधिक जांच करें जिन्होंने इन आपदाओं का मार्ग प्रशस्त किया।

नजरिया

डिजिटल दरबार में प्रकट बाबा कालभैरव की कृपा

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में बाबा कालभैरव को भगवान शिव का वह रौद्र और करुणामय स्वरूप माना जाता है, जो भक्तों के भय को हरकर उन्हें साहस, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। काशी के कोतवाल के रूप में उनकी महिमा अनादि काल से गाई जाती रही है। मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना काशी में कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। वे समय के स्वामी हैं, पापों का नाश करने वाले हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव जाग्रत रहते हैं। आज जब संसार तीव्र गति से डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, तब बाबा कालभैरव का दरबार भी नई तकनीक के माध्यम से अपने भक्तों के और निकट आ गया है। यह परिवर्तन केवल सुविधा नहीं, बल्कि भक्ति की एक नई अनुभूति है, जिसमें दूरी और परिस्थिति अब आस्था के मार्ग में बाधा नहीं बनती।

अनेक श्रद्धालु ऐसे हैं जो हृदय से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आर्थिक सीमाएं, व्यस्त जीवन या दूर देशों में निवास के कारण मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। उनके मन में यह पीड़ा रहती है कि वे बाबा की आरती और पूजा का प्रत्यक्ष लाभ नहीं ले पा रहे। ऐसे ही भक्तों के लिए अब ऑनलाइन विशेष पूजा और लाइव आरती की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। यह व्यवस्था उस भाव को साकार करती है कि यदि मन सच्चा हो, तो भगवान तक पहुंचने के लिए भौतिक दूरी कोई मायने नहीं रखती।

जब कोई भक्त कालभैरव मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूजा बुक करता है, तो वह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने विश्वास को डिजिटल माध्यम के सहारे मंदिर तक पहुंचा रहा होता है। सबसे पहले वह अपना पंजीकरण करता है, जिससे उसकी जानकारी सुरक्षित रहती है और उसे पूजा का प्रमाण प्राप्त हो सके। इसके बाद वह कालभैरव मंदिर का चयन कर विशेष पूजा का विकल्प चुनता है। यह चयन केवल तकनीकी कदम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प है कि वह अपनी श्रद्धा बाबा के चरणों में अर्पित करना चाहता है।

पूजा बुक करते समय भक्त अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना या समस्या का विवरण दर्ज करता है। यह वही परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जहां पंडित मंत्रोच्चार के साथ भक्त का नाम लेकर पूजा संपन्न करते हैं। जब निर्धारित समय पर पंडित जी वैदिक मंत्रों के साथ "फलाने गोत्र के अमुक नाम" का उच्चारण करते हैं, तो भक्त को यह अनुभव होता है कि उसकी प्रार्थना सीधे बाबा के श्रीचरणों में पहुंच रही है। डिजिटल माध्यम यहां केवल सेतु है, भावना वही प्राचीन और पवित्र है।

लाइव स्ट्रीम की सुविधा इस अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। निर्धारित समय पर जब भक्त अपने घर में दीपक जलाकर स्क्रीन के सामने बैठता है और मंदिर से प्रसारित होती आरती देखता है, तो वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि, शंखनाद, डमरू की गूंज और "जय कालभैरव" के जयघोष से घर का हर कोना मंदिर का आभास देने लगता है। कई भक्त बताते हैं कि उस क्षण उनकी आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं और हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव होता है।

कालभैरव की पूजा विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। जो लोग जीवन में बार-बार बाधाओं, भय, न्याय संबंधी समस्याओं या मानसिक अशांति से जूझ रहे हों, वे बाबा की शरण में आकर राहत अनुभव करते हैं। कालाष्टमी और भैरव अष्टमी के दिन तो विशेष महत्व रखते हैं। इन तिथियों पर ऑनलाइन पूजा की बुकिंग अधिक होती है, क्योंकि भक्त मानते हैं कि इन दिनों की गई आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है।

पूजा पूर्ण होने के बाद मंदिर की ओर से प्रसाद भक्त के पते पर भेजा जाता है। जब वह प्रसाद घर पहुंचता है, तो वह केवल मिठाई या पूजन सामग्री नहीं होता, बल्कि बाबा की कृपा का प्रतीक होता है।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम से राहत, ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने लागू की 'रिवर्स लेन' व्यवस्था

ठाणे। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पुल निर्माण कार्य के चलते मुंबई की ओर जाने वाली चार लेन की सड़क को घटाकर दो लेन किए जाने से भारी ट्रैफिक जाम की आशंका जताई जा रही थी। सुबह के रश आवर में ठाणे और आसपास के इलाकों से मुंबई जाने वाले यात्रियों को रोजाना लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन ठाणे ट्रैफिक पुलिस की रणनीतिक योजना और त्वरित निर्णयों से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है।

ट्रैफिक स्थिति का गहन अध्ययन करने के बाद पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे और ट्रैफिक

उपायुक्त पंकज शिरसाठ के मार्गदर्शन में सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच 'रिवर्स लेन' व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत मुंबई से ठाणे आने वाली एक लेन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और उसे ठाणे से मुंबई जाने वाले वाहनों के लिए खोल दिया गया।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो गया है और पहले लगने वाली वाहनों की लंबी कतारों से भी राहत मिली है। पहले घोड़बंदर, कल्याण और शहर के अन्य हिस्सों से आने वाली गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर घंटों तक फंसी रहती थीं, जिससे लोगों को समय से कार्यालय पहुंचने में दिक्कत होती थी। अब इस योजना से यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है।

हालांकि इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर तैनात रहकर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करनी पड़ रही है और लोगों को सही दिशा दिखाने के साथ अचानक उत्पन्न होने वाली स्थितियों को संभालना पड़ रहा है। ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल ने बताया कि यह व्यवस्था पूरी सावधानी और निगरानी के साथ संचालित की जा रही है।

ट्रैफिक उपायुक्त पंकज शिरसाठ ने बताया कि रिवर्स लेन का निर्णय सुबह के समय मुंबई की ओर बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो और यातायात सुचारू बना रहे। आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में यातायात व्यवस्था में और सुधार किए जाएंगे।

नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दो नाबालिग लड़कों ने किया गैंग रेप

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। यह घटना 5 फरवरी को नंदनवन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी के घर में हुई। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की आरोपी से पहले से पहचान थी। आरोपी ने 4 फरवरी को उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। लड़की इस विश्वास के साथ वहां गई कि घर पर आरोपी के परिवार के सदस्य भी मौजूद होंगे, लेकिन 5 फरवरी को जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने पहले उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसके साथ मौजूद दो अन्य नाबालिग आरोपियों ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया।

पीड़िता ने परिवार को बताई आपबीती

घटना के बाद डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब परिवार वालों ने उसे विश्वास में लेकर बात की तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार की शिकायत पर नंदनवन पुलिस स्टेशन में गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

पुलिस मामले की जांच कर रही

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को काउंसलिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

ई-गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में ज़िला परिषद ठाणे राज्य में तीसरे स्थान पर

ठाणे। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 150-दिन के ई-गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य के अलग-अलग सरकारी दफ़्तरों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया, और ज़िला

परिषद ठाणे ने राज्य में तीसरा स्थान हासिल करके शानदार सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस सफलता के लिए ज़िला परिषद ठाणे के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के साथ-साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। सभी विजेताओं को जल्द ही राज्य सरकार सम्मानित करेगी।इस मूल्यांकन में, ज़िला परिषद ठाणे ने सात ज़रूरी मानदंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे ऑफ़िस का ऑफ़िशियल वेबसाइट सिस्टम, 'आपले सरकार' सिस्टम, ई-ऑफ़िस, ऑफ़िस डैशबोर्ड,व्हाट्सएप चैटबॉट,एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जीआईसी सिस्टम का असरदार इस्तेमाल। डिजिटल गवर्नेंस की ओर यह कदम ठाणे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इनोवेटिव अप्रोच का सबूत है।

सिटी जोन मोबाइल शोरूम चोरी का 40 घंटे में खुलासा, दो गिरफ्तार

भिवंडी। शांतिनगर पुलिस ने गोपालनगर स्थित "सिटी जोन" मोबाइल शोरूम में 6 फरवरी की रात हुई सेंधमारी का 40 घंटे में पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने दीवार तोड़कर करीब 23.45 लाख रुपये के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किए थे।

पुलिस ने साहिद मोहम्मद उर्फ दंबग अंसारी (20) और उजेर अहमद खान (23) को गिरफ्तार कर उनके पास से 108 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप सहित 16.77 लाख रुपये का माल बरामद किया। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए कुछ सामान जलाने की भी कोशिश की थी। मामले की जांच जारी है।

एमबीबीएस परीक्षा में प्रथम शेट्टी की शानदार सफलता, शहर में हर्ष

भिवंडी। भिवंडी मनपा में भाजपा गुटनेता संतोष शेट्टी के सुपुत्र प्रथम शेट्टी ने एमबीबीएस परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया है। डी. वाय. पाटिल विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रथम का हाल ही में नवी मुंबई स्थित विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित समारोह में सम्मान किया गया।

कुलपति डॉ. शिवानी पाटिल और डीन डॉ. राजीव राव ने

उन्हें सम्मानित किया। प्रथम की इस उपलब्धि पर शहर के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र के लोगों ने संतोष शेट्टी व पूर्व नगरसेविका शशिलता शेट्टी को बधाई दी है।

परिवार ने बताया कि प्रथम ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर यह सफलता हासिल की है। उनकी कामयाबी से शहर में खुशी का माहौल है और युवाओं को प्रेरणा मिल रही है।

छात्रों का भविष्य संकट में भिवंडी जिला परिषद स्कूलों में एक शिक्षक पर चार कक्षाएं

भिवंडीः महाराष्ट्र के 'हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक' के दावे भिवंडी तालुका में खोखले साबित हो रहे हैं। पडघा केंद्र के समतानगर बोरीवली और भादाणे जिला परिषद मराठी स्कूलों में पहली से चौथी कक्षा तक के 24 से 31 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल एक-एक शिक्षक तैनात है। इस स्थिति में एक ही शिक्षक पर न केवल चार कक्षाओं के 14 विषय पढ़ाने का दबाव है, बल्कि उन्हें स्कूली पोषण आहार का प्रबंधन, ऑनलाइन रिकॉर्ड और डेटा एंट्री, प्रशासनिक और बैंकिंग कार्य, चुनाव संबंधी कार्य और विभिन्न प्रशिक्षण बैठकों जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं।

भादाणे स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रियंका पवार ने कहा, "एक ही व्यक्ति शिक्षक, प्रधानाध्यापक,

चपरासी और बी.एल.ओ. की भूमिका निभा रहा है। इसके बावजूद छात्रों की संख्या न बढ़ने का जिम्मा शिक्षकों पर डाला जाता है।" समतानगर (बोरीवली) में 31 छात्र हैं और एक ही शिक्षक, जबकि भादाणे में 24 छात्र हैं और केवल एक शिक्षक तैनात है। भिवंडी के गट शिक्षा अधिकारी संजय असावले ने बताया कि तालुका में लगभग 170 शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि 2012 के बाद से नियमित शिक्षक भर्ती नहीं हुई और हर महीने 2-3 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ी है।

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, तो अभिभावकों और सामाजिक संगठनों का आक्रोश बढ़ सकता है। नागरिकों का कहना है कि डिजिटल इंडिया और बेहतर शिक्षा की बातें तो सरकार करती है, लेकिन बुनियादी शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं।

पौराणिक गाथा 'महावतार' में विक्की कौशल का भव्य रूप चर्चा में

अभिनेता विक्की कौशल के लिए वर्ष 2025 उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरा है। ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा 'छावा' की अपार सफलता ने उन्हें बॉक्स ऑफिस के शीर्ष सितारों की कतार में ला खड़ा किया। फिल्म ने न केवल कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उनके अभिनय को लेकर समीक्षकों ने भी खुलकर सराहना की। उनके द्वारा निभाए गए किरदार की गंभीरता, शारीरिक भाषा और भावनात्मक गहराई ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। 'छावा' की सफलता के बाद से ही यह माना जा रहा है कि विक्की अब बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी आगामी फिल्म 'महावतार' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। इस समय विक्की कौशल संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' की तैयारियों में व्यस्त हैं। भंसाली की फिल्मों की भव्यता और भावनात्मक गहराई किसी से छिपी नहीं है, और ऐसे में विक्की का इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना उनके करियर के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, इसी बीच उनकी एक और बड़ी फिल्म 'महावतार' को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसने सिनेमा प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस फिल्म में विक्की भगवान विष्णु के छठे अवतार, चिरंजीवी परशुराम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह किरदार भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत शक्तिशाली और जटिल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। 'महावतार' को एक भव्य पौराणिक महाकाव्य के रूप में तैयार किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक कर रहे हैं, जो 'स्त्री' जैसी सफल फिल्म के लिए जाने जाते हैं। अमर कौशिक का नाम जुड़ने से यह संकेत मिलता है कि फिल्म में न केवल भव्यता होगी, बल्कि कहानी कहने का अंदाज भी प्रभावशाली और दर्शकों को बांधे रखने वाला होगा। पौराणिक कथाओं को आधुनिक तकनीक और सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती होती है, और मेकर्स इस चुनौती को पूरी तैयारी के साथ स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान परशुराम का चरित्र भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। वे एक योद्धा ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं, जिनके हाथ में परशु अर्थात फरसा रहता है। उनका जीवन धर्म, क्रोध, न्याय और तपस्या के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। ऐसे जटिल और प्रभावशाली चरित्र को पर्दे पर जीवंत करना किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं होता।

कठिन परिस्थितियों में राजपाल यादव के समर्थन में उतरा बॉलीवुड

हिंदी सिनेमा के चर्चित कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। वर्षों तक अपनी अदाकारी और हास्य शैली से दर्शकों को हंसाने वाले इस कलाकार की वास्तविक जिंदगी में फिलहाल गंभीर परेशानियां दस्तक दे चुकी हैं। भारी कर्ज, आर्थिक दबाव और लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई ने उनकी मुश्किलों को और गहरा कर दिया है। लगभग नौ करोड़ रुपये के वित्तीय संकट से जुड़े मामले में उन्हें हाल ही में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसने उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत को चौंका दिया। हालांकि इस कठिन समय में फिल्म इंडस्ट्री का रवैया यह दर्शाता है कि संकट की घड़ी में कलाकार अकेला नहीं होता। राजपाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे किरदारों से की थी, लेकिन अपनी अलग कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय के दम पर उन्होंने जल्द ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। 'हंगामा', 'चुप चुप के', 'भूल भुलैया', 'गरम मसाला' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे कलाकार की रही है, जो सीमित स्क्रीन टाइम में भी दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ देता है। ऐसे अभिनेता के जीवन में जब आर्थिक संकट जैसी स्थिति सामने आती है, तो यह इंडस्ट्री के लिए भी एक भावनात्मक क्षण बन जाता है। जैसे ही उनकी कानूनी और आर्थिक परेशानियों की खबर सामने आई, फिल्म जगत के कई प्रमुख नाम उनके समर्थन में आगे आए। अभिनेता सोनू सूद ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन जताया। सोनू सूद पहले भी जरूरतमंदों की सहायता के लिए जाने जाते रहे हैं, और इस बार उन्होंने अपने साथी कलाकार के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। उनके इस कदम के बाद अन्य कलाकारों ने भी एकजुटता का संदेश दिया। गुरमीत चौधरी और संगीत निर्माता राव इंद्रजीत सिंह ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इंडस्ट्री अपने सहयोगियों को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ती। रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे बड़े सितारों ने भी राजपाल यादव की सहायता के लिए आगे आने की इच्छा जताई है। भले ही इन सितारों ने औपचारिक बयान न दिया हो, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे आर्थिक और कानूनी स्तर पर मदद के विकल्प तलाश रहे हैं।

सीक्वल की चर्चाओं पर राजकुमार हिरानी ने तोड़ी चुप्पी

आमिर खान अभिनीत सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' और संजय दत्त की लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ी 'मुन्ना भाई' के तीसरे भाग को लेकर लंबे समय से सिनेमा जगत में चर्चाएं गर्म थीं। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक यह सवाल बार-बार उठता रहा कि क्या इन यादगार फिल्मों का सीक्वल सचमुच बनने जा रहा है। दर्शक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि रैंचो, फरहान और राजू की तिकड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटे या फिर मुन्ना और सर्किट की जोड़ी अपनी खास अंदाज में दर्शकों को हंसाए और भावुक करे। अब इन तमाम अटकलों के बीच निर्देशक राजकुमार हिरानी ने स्वयं सामने आकर स्थिति स्पष्ट की है। राजकुमार हिरानी हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा निर्देशकों में गिने जाते हैं, जिनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ गहरी सामाजिक संवेदनाएं भी देखने को मिलती हैं। 'मुन्ना भाई एमबीबीएस', 'लगे रहो मुन्ना भाई', '3 इडियट्स', 'पीके' और हालिया फिल्म 'डंकी' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई है। ऐसे में जब उनकी किसी पुरानी और सफल फिल्म के सीक्वल की चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बढ़ जाती है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हिरानी ने स्वीकार किया कि 'मुन्ना भाई 3' और '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर उनके मन में विचार जरूर हैं, लेकिन फिलहाल ये परियोजनाएं शुरुआती चरण में हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी इन फिल्मों पर औपचारिक रूप से काम शुरू नहीं हुआ है, बल्कि वे विभिन्न कहानियों और कॉन्सेप्ट्स पर मंथन कर रहे हैं। हिरानी के अनुसार, किसी भी फिल्म को बनाने से पहले वे उसकी कहानी को पूरी तरह से संतोषजनक रूप देना चाहते हैं, ताकि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। 'मुन्ना भाई 3' को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास एक मजबूत और व्यापक विचार मौजूद है। यह कहानी बड़े पैमाने पर सोची गई है और इसमें भावनात्मक गहराई के साथ मनोरंजन का वही पुराना अंदाज बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कहानी का अंत अभी तक पूरी तरह तय नहीं हो पाया है। जब तक स्क्रिप्ट उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करती, तब तक वे फिल्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हिरानी का मानना है कि किसी भी सफल फ्रेंचाइज़ी का अगला भाग तभी बनना चाहिए, जब उसके पास कहने के लिए कुछ नया और प्रभावशाली हो। दूसरी ओर, '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर भी उन्होंने दिलचस्प जानकारी साझा की। हिरानी ने बताया कि हाल ही में अचानक उनके मन में एक नया विचार आया, जिसने उन्हें इस कहानी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इस विचार पर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा हुई है, लेकिन फिल्म अभी केवल आइडिया स्टेज पर है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस समय तीन से चार अलग-अलग स्क्रिप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पहले आगे बढ़ेगा, यह तय होना अभी बाकी है। '3 इडियट्स' साल 2009 में रिलीज हुई थी और यह भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म ने शिक्षा व्यवस्था, करियर के दबाव और दोस्ती के महत्व जैसे विषयों को संवेदनशीलता और हास्य के साथ प्रस्तुत किया था। आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी की तिकड़ी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। ऐसे में यदि इस फिल्म का सीक्वल बनता है, तो उससे जुड़ी अपेक्षाएं भी बेहद ऊंची होंगी। हिरानी इस बात से भलीभांति परिचित हैं और इसलिए वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। इसी तरह 'मुन्ना भाई' श्रृंखला ने भी भारतीय सिनेमा को एक नया दृष्टिकोण दिया था। 'जादू की झप्पी' और 'गांधीगिरी' जैसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा बन गए थे। संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी ने हास्य और भावनात्मकता का ऐसा संगम पेश किया, जो आज भी दर्शकों को याद है। 'लगे रहो मुन्ना भाई' के बाद से तीसरे भाग की चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब हिरानी के बयान ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि यह इंतजार शायद ज्यादा लंबा न हो। राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्म 'डंकी' वर्ष 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म अवैध प्रवास और सपनों की तलाश जैसे विषयों पर आधारित थी। 'डंकी' के बाद से ही दर्शक यह जानने को उत्सुक थे कि हिरानी अगला कदम क्या उठाएंगे। उनके हालिया बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि वे एक साथ कई विचारों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही किसी एक प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देंगे।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail com

नई महापौर के पदभार के साथ ही अवैध अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका में महापौर और उपमहापौर के चुनाव संपन्न होते ही शहर में प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। नई महापौर के पदभार ग्रहण करते ही अवैध निर्माण और फेरीवालों के खिलाफ सख्त अभियान की शुरुआत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मनपा प्रशासन अब अतिक्रमण के मुद्दे पर किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बुधवार को मुलुंड स्टेशन परिसर में व्यापक कार्रवाई करते हुए 61 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और करीब 1100 वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई को नई महापौर की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की रितु तावड़े ने महापौर पद संभालने के बाद अपने पहले बयान में ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और अवैध फेरीवालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि शहर की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर अतिक्रमण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के तुरंत

बाद मुलुंड में हुई कार्रवाई ने उनके बयान को ठोस रूप में सामने ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस कदम को प्रशासनिक सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

मनपा के 'टी' विभाग द्वारा 11 फरवरी 2026 को मुलुंड (पश्चिम) स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग पर विशेष अभियान चलाया गया। मुलुंड स्टेशन के आसपास का इलाका लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था। फुटपाथों पर अवैध ढांचे खड़े होने से पैदल यात्रियों को आवाजाही में कठिनाई हो रही थी और यातायात भी प्रभावित हो रहा था। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की योजना बनाई।

अभियान के दौरान 61 अवैध निर्माणों को हटाया गया। इनमें अस्थायी ढांचे, टीन शेड, अवैध दुकानों के विस्तार और अन्य अनधिकृत संरचनाएं शामिल थीं। कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 1100 वर्ग मीटर क्षेत्र को खाली कराया गया। अधिकारियों के अनुसार यह इलाका सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और यहां किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नियमों के विरुद्ध है। खाली कराए गए क्षेत्र को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

यह पूरी कार्रवाई उपायुक्त (परिमंडल-6) संतोषकुमार धोंडे की निगरानी में और सहायक आयुक्त ('टी' विभाग) योगिता कोल्हे के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान में 'टी' प्रशासनिक विभाग के विभिन्न शाखाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 4 जेसीबी, 7 डंपर और अन्य आवश्यक मशीनरी का उपयोग किया गया। करीब 70 अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था, जिससे कानून-व्यवस्था बनी रही और कार्रवाई बिना किसी बड़े विरोध के पूरी हो सकी।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। एक ओर जहां कई नागरिकों ने फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने का स्वागत किया है, वहीं कुछ प्रभावित लोगों ने अपनी आजीविका पर असर पड़ने की चिंता जताई है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे या जिन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक विस्तार कर लिया था, उन्हीं पर कार्रवाई की गई। मनपा प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह अभियान केवल एक शुरुआत है और शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

कुर्ला स्टेशन पर टीसी की फुर्ती से टला बड़ा हादसा

मुंबई। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं और इन्हें शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। भीड़भाड़ और जल्दबाजी के बीच अक्सर जोखिम भरे हालात भी बन जाते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी एक व्यक्ति की सतर्कता और साहस बड़ा हादसा टाल देता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला मध्य रेल के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर सामने आया, जहां ड्यूटी पर तैनात एक टिकट कलेक्टर की फुर्ती ने एक बुजुर्ग महिला यात्री की जान बचा ली। यह घटना 7 फरवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे की है। सीएसएमटी की ओर जाने वाली एक लोकल ट्रेन कुर्ला स्टेशन से रवाना हो रही थी। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म छोड़कर रफ्तार पकड़नी शुरू की, उसी समय एक बुजुर्ग महिला यात्री, जिनकी पहचान बेबी भास्कर गायकर के रूप में हुई है, चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगीं। भीड़ और जल्दबाजी के बीच उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसल गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने खतरनाक गैप की ओर खिंचती चली गईं। स्थिति बेहद गंभीर थी और कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था। उसी समय प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर (सीसीटीसी) जॉन पॉल की नजर इस घटना पर पड़ी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए बिजली की तेजी से दौड़ लगाई और गिरती हुई महिला को पीछे की ओर जोर से खींच लिया। महिला का शरीर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जाने ही वाला था, लेकिन जॉन पॉल की तत्परता ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो बाद में रेलवे प्रशासन ने जारी किया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ सेकंड की सतर्कता ने एक जान बचा ली।

इस साहसिक प्रयास के दौरान जॉन पॉल खुद भी चोटिल हो गए। महिला को खींचते समय उनके कंधे में मोच आ गई, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह किए बिना पहले महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की। आसपास मौजूद अन्य यात्रियों ने भी तुरंत मदद की और महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हादसे के बाद महिला सदमे में थीं। उन्हें तुरंत टिकट कलेक्टर कार्यालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया और पानी पिलाकर उनकी स्थिति सामान्य की गई।

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर क्या किया गया?:सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर शुरू हुए विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक नया झटका दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के मामले में रिपोर्ट मांगी और पूछा कि 2024 में संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में सब-कैटेगरी और क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की अनुमति दी थी, ताकि आरक्षण के लाभ समान रूप से वितरण किए जा सकें। इस फैसले में राज्य सरकारों को अपने आरक्षण कोटे के भीतर सब-कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर लागू करने का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू कराने की मांग समता आंदोलन समिति और ओपी शुक्ला ने की थी। मंगलवार 10 फरवरी को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र से स्पष्ट जवाब मांगा।

राजनीतिक पटल पर यह फैसला काफी विवादित रहा। कांग्रेस और कई NDA सहयोगी दलों ने इसे विरोध किया, जबकि बसपा प्रमुख मायावती और दलित संगठन सड़क पर उतर आए। लगभग 100 NDA सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान में SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है और सरकार संविधान के अनुसार कार्रवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की इस मांग ने मोदी सरकार को नए राजनीतिक और संवैधानिक दबाव में डाल दिया है, और अब आरक्षण के इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र को जवाब देना अनिवार्य हो गया है।

केंद्र सरकार के श्रम कानूनों के खिलाफ कल के 'भारत बंद' को कांग्रेस का समर्थन

मुंबईः केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के खिलाफ देशभर में तीव्र विरोध हो रहा है। इन श्रम कानूनों के विरोध में देश की 10 प्रमुख श्रमिक संगठनों ने गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। इस भारत बंद को विभिन्न किसान संगठनों का भी समर्थन मिला है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इस बंद को समर्थन देने की घोषणा की है।

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों से मजदूरों के सामने कई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस के अनुसार, नए बदलावों के कारण श्रमिकों को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां किसान और मजदूर विरोधी हैं।

इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के निर्देशानुसार कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भारत बंद में सक्रिय रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन व प्रशासन) गणेश पाटील ने दी है।

विश्वशांति गुरुकुल में विश्वधर्मी विश्वनाथ सभागृह का उद्घाटन, पद्मश्री गंगावणे ने विद्यालय की प्रशंसा की

नवी मुंबई। आधुनिक शिक्षा और भारतीय ज्ञान-परंपरा का समन्वय करने वाला एमआईटी विश्वशांति गुरुकुल अपने विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कृति और भारतीय मूल्यों का संस्कार देने के लिए जाना जाता है। गुरुकुल में हाल ही में नव-निर्मित 'विश्वधर्मी विश्वनाथ सभागृह' का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री परशुराम गंगावणे ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यह विद्यालय विद्यार्थियों को न केवल आधुनिक शिक्षा देता है बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को भी विकसित करता है। उन्होंने कहा कि चित्रकथी

और कठपुतली जैसी पारंपरिक कला रूप केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज प्रबोधन का माध्यम रही हैं।

इस अवसर पर एमआईटी शिक्षा समूह के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रो। डॉ। विश्वनाथ कराड, उनकी पत्नी सौ। उषा विश्वनाथ कराड, ट्रस्टी एवं महासचिव प्रो। स्वाती कराड चाटे, पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व संचालक राजेंद्र पाटील सहित विद्यालय की प्रधानाचार्या अंशू सक्सेना, अकादमिक हेड शीतल वर्मा और अन्य शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित थे।

प्रो। स्वाती कराड चाटे ने कहा कि नव-निर्मित सभागृह संस्थापक की दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह सभागृह शैक्षणिक गुणवत्ता, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विश्वशांति गुरुकुल के इस प्रयास से शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदार नागरिक बनने की समझ विकसित होगी।

मुंबई महापालिका की पहली बैठक में कांग्रेस पार्षदों को जगह नहीं मिलने पर वर्षा गायकवाड़ का BJP पर हमला

मुंबई। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई महापालिका की पहली बैठक को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुंबई महापालिकेत पहली बार बीजेपी की सत्ता आई और लोकतंत्र का गला घोंटना शुरू हो गया! आज महापालिका की पहली बैठक में कांग्रेस के २४ पार्षदों को बैठने की जगह नहीं दी गई। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को पहले दिन ही सीट न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है।

वर्षा गायकवाड़ के इस ट्वीट से महापालिका में विपक्षी पार्षदों के साथ होने वाले असंतोष और बीजेपी की प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठ गए हैं। इस घटना ने महापालिका की शुरुआत से ही राजनीतिक बहस को जन्म दिया है और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है।

मध्य रेलवे ने 10 माह में वसूले 203 करोड़ रुपये, बिना टिकट यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई

मुंबई। मुंबई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए मध्य रेलवे ने 2025-26 में अपने पूरे नेटवर्क पर गहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान अब तक कुल 203 करोड़ 76 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. स्वप्निल नीला के अनुसार, अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 34.34 लाख अवैध यात्रा के मामले पकड़े गए। इससे पहले 2024-25 में 31.28 लाख मामले दर्ज किए गए थे और 167 करोड़ 61 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया था। इस बार जुर्माने में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

मंडलवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

- भुसावल डिवीजनः 8.18 लाख यात्रियों से 68.86 करोड़
- मुंबई डिवीजनः 14.51 लाख मामलों में 62.73 करोड़
- पुणे डिवीजनः 3.84 लाख यात्रियों से 23.73 करोड़
- नागपुर डिवीजनः 3.68 लाख यात्रियों से 22.91 करोड़
- सोलापुर डिवीजनः 2.06 लाख यात्रियों से 16.06 करोड़

मुंबई डिवीजन में 10 महीनों में 9.49 लाख यात्रियों से 27.39 करोड़ रुपये वसूले गए। जनवरी माह में 1.14 लाख अवैध यात्रियों पर कार्रवाई कर 3.42 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल प्रशासन ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ अवैध यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होली और शिमोत्सव के मौके पर कोंकण जाने वाली एसटी बसों की संख्या बढ़ाई गई, यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं

मुंबई। होली और कोंकण के पारंपरिक उत्सव 'शिमोत्सव' के आगमन के साथ ही मुंबई में रहने वाले कोंकणवासियों की घर वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारी भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने मुंबई और उपनगरों से कोंकण के लिए सैकड़ों अतिरिक्त एसटी बसें चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा 27 और 28 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

एसटी प्रशासन ने दिन और रात दोनों समय के लिए बसों का शेड्यूल तैयार किया है, ताकि नौकरीपेशा लोग भी काम के बाद सीधे अपने गांव निकल सकें। मुंबई महानगर क्षेत्र के प्रमुख डिपो और रूट इस प्रकार हैं:

- मुंबई सेंट्रलः कासे, खेड़, गुहागर और दापोली के लिए देर रात तक बसें।
- परेल डिपोः दापोली, देवरुख

और खेड़ रूट के लिए विशेष सेवाएं।

- कुर्ला-नेहरू नगर और सायनः गुहागर, खेड़ और दापोली के लिए अतिरिक्त ट्रिप्स।
- ठाणे (CBS): महाड, साखरपा, गुहागर और दापोली के लिए रात 9-10 बजे विशेष बसें।
- बोरीवली, नालासोपारा और विट्ठलवाड़ीः सुबह और रात दोनों समय पर्याप्त बसें।

सरकारी योजनाओं का लाभ:

- महिला सम्मान योजनाः महिलाएं बस किराए में 50% छूट की हकदार।
- अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनाः 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
- वरिष्ठ नागरिक रियायतः 65-75 वर्ष के नागरिकों को 45% छूट।

एसटी प्रशासन ने यात्रियों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की है। संवेदनशील रूटों पर अतिरिक्त स्टैंडबाय बसें भी रखी गई हैं ताकि तकनीकी खराबी या अचानक भीड़ में कोई परेशानी न हो।

2029 में बिजली घटाने का दावा झूठा, 16% महंगी होगी बिजली : अतुल लोंढे

मुंबईः कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य में बिजली दर 5 साल में 50% तक घटाने और पहले साल 10% कटौती का वादा किया था, लेकिन अब हकीकत इसके उलट है। लोंढे के अनुसार, बिजली दर कम होने के बजाय 16% तक बढ़ने जा रहे हैं।

टिळक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महावितरण (MSEDCL) ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के समक्ष 20 से 40% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में नागपुर में जनसुनवाई भी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा प्रयास अदानी के फायदे के लिए किया जा रहा है, जिससे आम बिजली उपभोक्ता, छोटे-मध्यम उद्योग और

व्यापारी वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा।

लोंढे ने कहा कि महाराष्ट्र में बिजली दर देश में सबसे महंगे हैं, जबकि गुजरात, कर्नाटक और तेलंगणा जैसे राज्यों में बिजली महाराष्ट्र से सस्ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली उत्पादन की लागत लगभग समान है, तो महाराष्ट्र में बिजली दर इतनी अधिक क्यों हैं।

उन्होंने MERC के बहुवर्षीय दर निर्धारण (MYT) आदेश को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और मांग की कि 25 जून 2025 का संशोधित आदेश रद्द कर 28 मार्च 2025 वाला पुराना आदेश लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से हस्तक्षेप कर दोबारा जनसुनवाई कराने और उद्योगों व उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की।

मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में रत्नागिरी से आई आम की रानी 'अल्फांजों' को बेचता हुआ फल विक्रेता ।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (साउथ) पर अमरसन्स गार्डन से ब्रेच कैंडी तक के 'मेलोडी रोड' खंड का उद्घाटन किया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दो नाबालिग लड़कों ने किया गैंग रेप

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। यह घटना 5 फरवरी को नंदनवन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी के घर में हुई। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक,

पीड़िता की आरोपी से पहले से पहचान थी। आरोपी ने 4 फरवरी को उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। लड़की इस विश्वास के साथ वहां गई कि घर पर आरोपी के परिवार के सदस्य भी मौजूद होंगे, लेकिन 5 फरवरी को जब वह वहां पहुंची तो आरोपी ने पहले उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसके साथ मौजूद दो अन्य नाबालिग आरोपियों ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया।

पीड़िता ने परिवार को बताई आपबीती

घटना के बाद डर के कारण पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में जब परिवार वालों ने उसे विश्वास में लेकर बात की तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार की शिकायत पर नंदनवन पुलिस स्टेशन में गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

पुलिस मामले की जांच कर रही

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को काउंसलिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।